HRA AN USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

818

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रमार, फरवरी 15, 2002/मार्च 26, 1923 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

No. 24]

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अ**धिस्**चना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

सं. टीएएमपी/31/2001-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास में अल्याविध लाइसेंस के आधार पर आधा खंडजा बिछे स्टैकयार्ड को शासी लाइसेंस देने की दरों के मान में संशोधन करता है।

महापत्तन प्रशुएक प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/31/2001-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)

आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2002 के 8वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने मामला सं. टीएएमपी/31/2001-एनएमपीटी में 5 नवंबर, 2001 को न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) में अल्पाविध लाइसेंस के आधार पर आधा खंडजा बिछे स्टैकयार्ड को शासी लाइसेंस देने की दरीं के मान का अनुमोदन करने का आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खंड-4) में 3 दिसम्बर, 2001 को राजपत्र सं. 324 द्वारा अधिसृचित किया गया था।

- 2. महापत्तन न्यासों की जमीनों को पट्टे पर देने के लिए इस प्राधिकरण ने अभी तक अपने मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए हैं। इसलिए, इस प्राधिकरण ने अपने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाने तक भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए हैं।
- 3. एनएमपीटी में अल्पाविध लाइसेंस के आधार पर आधा खंडजा बिछे स्टैकयार्ड को शासी लाइसेंस देने की दरों के मान को अधिसूचित करते समय, लाइसेंस शुल्क में वार्षिक वृद्धि और प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टे की आधार दर के पुनर्निधारण के लिए सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपलब्ध

उपबंध असावधानीवश छूट गए थे। इसी प्रकार, खुले क्षेत्र के लिए 600/- रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर प्रतिमाह के लाइसेंस शुल्क पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (चक्रवृद्धि) की दर से वार्षिक वृद्धि होगी, इस तथ्य को 20 फरवरी, 1997 के कर्नाटक के राजपत्र में इसकी अधिसचना में भी अलग से नहीं दर्शाया गया था।

- 4. असावधानीवश हुई त्रुटियों में सुधार करने के लिए, अब 5 नवम्बर, 2001 के पूर्व आदेश में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इसलिए, यह प्राधिकारण 5 नवम्बर, 2001 के पूर्व आदेश में निम्निलिखित संशोधनों/सुधारों का अनुमोदन करता है:—
 - पैरा 7.1. (i), को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:—
 "एनएमपीटी की दरों के मान में अधिसूचित खुले क्षेत्र के लिए यथा लागू मासिक लाइसेंस शुल्क का फरवरी, 2000 से 2 दिसम्बर,
 2001 तक पूर्व प्रभाव से अनुमोदन।"
 - (ii) पैरा 7.1. (ii) के नीचे निम्नलिखित भया पैरा 7.1. (iii) जोड़ा जाता है :—
 - ''लाइसेंस शुल्क में 3 दिसम्बर, 2001 से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ('चक्रवृद्धि) की वृद्धि होगी। एनएमपीटी के पास प्रत्येक पांच वर्ष में लाइसेंस की आधार दर का पुनर्निधारण करने का विकल्प होगा।''

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2002

No. TAMP/31/2001-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates governing licensing of semi-paved stackyard on short-term licence basis at the New Mangalore Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/31/2001-NMPT

The New Mangalore Port Trust (NMPT)

ORDER

Applicant

(Passed on this 8th day of February, 2002

This Authority had passed an Order on 5 November, 2001 in case No. TAMP/31/2001-NMPT approving the Scale of Rates governing licensing of semi-paved stackyard on short-term licence basis at the New Mangalore Port Trust (NMPT). This Order was notified in the Gazette of India, Extraordinary (Part III Section 4) on 3 December, 2001 vide Gazette No. 324.

- 2. This Authority has not yet prescribed its own guidelines governing leasing of lands of the major port trusts. This Authority has, therefore, adopted the guidelines in this regard issued from time to time by the Government of India in the Ministry of Shipping until formulation of its own guidelines.
- 3. While notifying the Scale of Rates governing licensing of semi-paved stackyard on short-term licence basis at the NMPT, the provisions available in the Government guidelines for an annual escalation in the licence fee and also re-fixation of base rate of lease every five years were inadvertently omitted. Likewise, the fact that the licence fee of Rs. 600/- per 100 sq. metre per month for open space is subject to an annual escalation @ 5% p.a. (compounded) from its notification in the Karnataka Gazette dated 20 February 1997 has also not been specifically indicated.
- 4. In order to rectify the errors that crept in due to oversight, it has now become necessary to amend the earlier Order dated 5 November 2001. This Authority, therefore, approves the following amendments/modifications to the earlier Order dated 5 November, 2001:
 - (i) Paragraph 7.1. (i) is deleted and substituted by the following:
 - "Approval of a monthly licence fee as applicable for open space notified in the Scale of Rates of the NMPT with retrospective effect from February, 2000 till 2 December 2001".
 - (ii) A new paragraph 7.1.(iii) as follows is added below paragraph 7.1.(ii):
 - "The licence fee shall bear an escalation @ 5% (compoundable) per annum with effect from 3 December 2001. The NMPT will have an option to re-fix the base rate of the licence fee every five years".

S. SATHYAM, Chairman [ADVT/III/IV/143/2001/Exty.]